>

Title: Need to grant early clearance/N.O.C. from M/o Environment & Forests for the development works being carried out in Himachal Pradesh, J&K and Uttarakhand.

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा) हि.प्र., जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड सहित सभी पर्वतीय राज्यों में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सभी विकास कार्यों चाहे सड़क निर्माण हो या भवन निर्माण, महिला मंडल भवन हों चाहे खेल मैदान, शिक्षण संस्थाओं का निर्माण हो या स्वास्थ्य संस्थाओं का, सामाजिक संस्थाएं हों या धार्मिक संस्थाएं, सिंचाई योजनाएं हो या जलापूर्ति योजनाएं, सभी प्रकार के कार्यों में अनापत्ति प्रमाण पत्र (No objection certificate) न देने या अत्याधिक देरी से दिए जाने के कारण सभी प्रकार का विकास रूकने के कगार पर खड़ा हो गया है तथा वन की नई परिभाषा ""All the waste land is forest land " आने से तो विकास कार्य हो ही नहीं पाएंगे। अतः इस गंभीर परिस्थिति से भारत की जनता विशेषकर पहाड़ी राज्यों की जनता को निजात दिलाने हेतु भारत सरकार से तुरन्त समुचित कार्यवाही करने का विशेष आग्रह कर रहा हूँ।